

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 78 हजार से अधिक उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में वृद्धि (90 रु० से बढ़ाकर 125 रु० प्रति कुन्तल) कार्यक्रम को सम्बोधित किया

उचित दर विक्रेता शासन और जनता-जनार्दन के बीच सेतु तथा शासन की योजनाओं को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने का कार्य करते : मुख्यमंत्री

आज प्रदेश के लगभग 80 हजार उचित दर विक्रेताओं को मार्जिन मनी में 30 प्रतिशत वृद्धि का उपहार मिल रहा

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से प्रदेश में 15 करोड़ लोग निःशुल्क राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे, निराश्रित और दिव्यांगजन, जो दुकान तक नहीं आ सकते, उनके राशन को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही

जब व्यवस्था स्पष्ट और पारदर्शी होती, तो किसान, नौजवान, महिला तथा समाज के प्रत्येक वर्ग को शासन की योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त होता

ग्राम पंचायत में बनने वाले अन्नपूर्णा भवन के संचालक के रूप में उचित दर विक्रेताओं को जो उचित सम्मान प्राप्त होने जा रहा, वह उनके कार्यों, परिश्रम और प्रयासों का परिणाम

सरकार द्वारा निराश्रित, गरीब, जरूरतमन्द और दिव्यांगजन सहित सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें शासन की योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जा रहा

प्रदेश का परसेप्शन ठीक हो और उचित दर विक्रेताओं के बारे में लोगों की धारणा बदले, इसी उद्देश्य से वर्ष 2017 में ई-पॉस मशीन लगानी प्रारम्भ की गई

सरकार और उचित दर विक्रेता के बीच किसी मीडिएटर व बैरियर की व्यवस्था नहीं, पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई गई, जिससे उचित दर विक्रेताओं का सम्मान बढ़ा

प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उचित दर विक्रेताओं की दुकानों को अन्नपूर्णा भवन के रूप में निर्मित किया जा रहा, इसके लिए इस वर्ष 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था

अन्नपूर्णा भवन में दुकान के साथ वेयर हाउस की व्यवस्था होगी, उचित दर विक्रेता राशन के साथ 39 प्रकार के आइटम बेच सकते

मुख्यमंत्री ने स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया, 'लोकल को ग्लोबल' बनाने का प्रयास ग्राम पंचायत तथा स्वयं के स्तर से प्रारम्भ किया जा सकता

प्रदेश में 02 करोड़ परिवारों को रसोई गैस तथा 1.53 करोड़ परिवारों को बिजली कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध, 10,000 राशन की दुकानों को अन्नपूर्णा भवन के रूप में स्थापित

लखनऊ : 17 अगस्त, 2026

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज प्रदेश के लगभग 80 हजार उचित दर विक्रेताओं को मार्जिन मनी में 30 प्रतिशत वृद्धि का उपहार मिल रहा है। उचित दर विक्रेता व फेयर प्राइस

शॉप के संचालक शासन और जनता-जनार्दन के बीच सेतु तथा शासन की योजनाओं को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने का कार्य करते हैं। जब व्यवस्था स्पष्ट और पारदर्शी होती है, तो किसान, नौजवान, महिला तथा समाज के प्रत्येक वर्ग को शासन की योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त होता है। यही व्यवस्था विश्वास का कारण बनती है। इससे लोकतंत्र पुष्ट एवं मजबूत होता है।

मुख्यमंत्री जी आज यहां लोक भवन में उत्तर प्रदेश के 78 हजार से अधिक उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में वृद्धि (90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति कुन्तल) करने के उपरान्त आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी के अन्तर्गत ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहली बार उचित दर विक्रेताओं के लिए मार्जिन मनी में 30 प्रतिशत की वृद्धि का कार्य केन्द्र और राज्य सरकार ने किया है। ग्राम पंचायत में बनने वाले अन्नपूर्णा भवन के संचालक के रूप में उन्हें जो उचित सम्मान प्राप्त होने जा रहा है, वह उचित दर विक्रेताओं के कार्यों, परिश्रम और प्रयासों का परिणाम है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार है। देवाधिदेव महादेव के प्रति हम सभी की श्रद्धा और उनकी उपासना इस बात के लिए प्रेरित करती है कि 'शिवो भूत्वा शिवं यजेत' अर्थात् शिव की पूजा का मतलब शिव की तरह हो जाना, शिव में एकाकार हो जाना और उसमें लय हो जाना है। ईश्वर ने हमें दायित्व सौंपा है कि अपने कार्यों के माध्यम से समाज की सेवा करें। शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री जब गरीब तक पहुंचती है, तो प्रसन्नता होती है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित, गरीब, जरूरतमन्द और दिव्यांगजन सहित सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें शासन की योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। आजीविका कमाने का माध्यम हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सदैव वही कार्य करना चाहिए जिसमें सम्मान हो। ऐसे कार्य का पीढ़ियों पर प्रभाव पड़ता है। कार्य अगर सम्मान न दिलाए, तो कम से कम उस कार्य के कारण अपमान महसूस न हो, यह जरूर ध्यान में रखना चाहिए। आज उचित दरविक्रेताओं को उनके कार्य के कारण सम्मान मिल रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उचित दर विक्रेताओं को लोग शक की निगाहों से देखते थे। 'कोटेदार' शब्द से ही लोगों में चिढ़ होने लग गई थी। इसमें गलती उचित दर विक्रेताओं की नहीं थी। उस समय सत्ता में बैठे लोगों की नीयत में खोट और भ्रष्ट आचरण की आंच से उचित दर विक्रेता चाहकर भी अपने आपको बचा नहीं पाते थे। लूट किसी और की होती थी, लेकिन खामियाजा उचित दर विक्रेताओं को भुगतना पड़ता था।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यही स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश की थी। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के नागरिक प्रदेश से बाहर जाते थे, तो उन्हें शक की निगाहों से देखा

जाता था। विगत 09 वर्षों में उत्तर प्रदेश के बारे में ओवरऑल परसेप्शन बदला है। देश-दुनिया में उत्तर प्रदेश का नाम लेने पर जो लोग पहले दूरी बनाते थे, वह आज 10 कदम आगे आकर गले मिलना चाहते हैं। यह परिवर्तन डबल इंजन सरकार की उस ताकत का परिणाम है, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश और प्रदेश ने सामूहिक रूप से अर्जित किया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश का परसेप्शन ठीक हो और उचित दर विक्रेताओं के बारे में लोगों की धारणा बदले, इसी उद्देश्य से वर्ष 2017 में ई-पॉस मशीन लगानी प्रारम्भ की गई। एफ0सी0आई0 के गोदाम से सीधे कोटे की दुकान तक सिंगल डोर-स्टेप डिलीवरी के माध्यम से राशन पहुंचाने की कार्यवाही शुरू हुई। सरकार और उचित दर विक्रेता के बीच किसी मीडिएटर या बैरियर की व्यवस्था नहीं रखी गई। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई गई, जिससे उचित दर विक्रेताओं का सम्मान बढ़ा। आज गांव में लोग उनके सुख-दुःख में साथ खड़े होते हैं और उनका सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उचित दर विक्रेताओं की दुकानों को अन्नपूर्णा भवन के रूप में निर्मित किया जा रहा है। इसके लिए इस वर्ष 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अन्नपूर्णा भवन में दुकान के साथ वेयर हाउस की व्यवस्था भी होगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले उचित दर विक्रेता केवल राशन की बिक्री करते थे। अब वह 39 प्रकार के आइटम अपनी दुकान में बेच सकते हैं। समाज एवं देश पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सामाग्री बेचने पर रोक है। कपड़े, साबुन, टूथपेस्ट, तेल सहित अन्य सामान उचित दर की दुकान से बेचे जा सकते हैं। उन्होंने उचित दर विक्रेताओं से कहा कि वह अपने यहां अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण की कार्यवाही तेजी से आगे बढ़ाएं। राज्य सरकार समय से धनराशि का आवंटन करेगी। अच्छे भवन और वेयर हाउस बनाए जाएंगे। अन्नपूर्णा भवनों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने से इसके और बेहतर परिणाम सामने आएंगे। राशन वितरण का कार्य एक सप्ताह से 10 दिन में पूरा किया जा सकता है। शेष समय में वेयर हाउस का अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इससे अतिरिक्त आय भी अर्जित की जा सकती है।

स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 'लोकल को ग्लोबल' बनाने का प्रयास ग्राम पंचायत तथा स्वयं के स्तर से प्रारम्भ किया जा सकता है। 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना' के उत्पादों को भी अन्नपूर्णा भवनों में रखा जा सकता है। होली, दीपावली और अन्य पर्व-त्योहारों पर स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने से स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इन भवनों में नशीले पदार्थों और फायर सेफ्टी से जुड़े ज्वलनशील पदार्थों को छोड़कर अन्य मामलों में कोई रोक-टोक नहीं है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले उचित दर विक्रेताओं को लाभांश के रूप में 70 रुपये प्रति कुन्तल मिलते थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 90 रुपये प्रति कुन्तल किया गया। अब भारत सरकार ने इस मार्जिन मनी को 10 रुपये तथा प्रदेश सरकार ने 25 रुपये

बढ़ाने का कार्य किया है। अब उचित दर विक्रेताओं को लाभांश के रूप में कुल 125 रुपये प्रति कुन्तल प्राप्त होंगे। इस प्रकार कुल 35 रुपये की वृद्धि हो रही है। प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से 25 रुपये और बढ़ाने के लिए भी अनुरोध किया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सामान्यतः प्रत्येक उचित दर विक्रेता के यहां लगभग 100 कुन्तल राशन का आवंटन हो जाता है। पहले लगभग 90 रुपये प्रति कुन्तल के हिसाब से उन्हें भुगतान किया जाता था, जिससे लगभग 12,750 रुपये प्रतिमाह की आय होती थी। अब 125 रुपये प्रति कुन्तल के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। यदि कोई उचित दर विक्रेता 100 कुन्तल राशन वितरित करता है तो उसे केवल इसी मद से 16,250 रुपये प्राप्त होंगे। इसके अलावा दुकान पर अन्य सामान की बिक्री से होने वाला मुनाफा अलग होगा। अधिक बिक्री करने पर उचित दर विक्रेता अधिक मुनाफा कमा सकते हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में भूख से अनेक मौतें होती थीं। गरीब का राशन कार्ड कोई न कोई अपने घर में रख लेता था और गरीब भूख से मरता था। आज ऐसी स्थिति नहीं है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से प्रदेश में 15 करोड़ लोग निःशुल्क राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। निराश्रित और दिव्यांगजन, जो दुकान तक नहीं आ सकते, उनके राशन को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है।

प्रदेश में 02 करोड़ परिवारों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। 01 करोड़ 53 लाख परिवार, जिन्हें कभी बिजली के कनेक्शन नहीं मिल पाए थे, उन्हें निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। 10 हजार राशन की दुकानों को अन्नपूर्णा भवन के रूप में स्थापित किया गया है। इस वर्ष इन कार्यों के लिए अतिरिक्त 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में जिन क्षेत्रों में व्यापक रिफॉर्म हुए हैं, उनमें खाद्य एवं रसद विभाग भी शामिल है। वर्ष 2017 से पहले जनता दर्शन कार्यक्रम में यदि 1,000 एप्लीकेशन आती थीं, तो लगभग 300 शिकायतें राशन से सम्बन्धित विसंगतियों की होती थीं। आज खाद्य एवं रसद विभाग से सम्बन्धित राशन वितरण की एक भी शिकायत नहीं आती। यह उचित दर विक्रेताओं का सम्मान है। अब कोई उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना काल के दौरान उद्योग-धन्धे बन्द हो गये थे, उस समय भी उचित दर विक्रेता राशन वितरित कर रहे थे। दाल, नमक और तेल वितरण की योजना लागू की गई थी। किसी स्थान से शिकायत नहीं आयी कि किसी गरीब तक तेल, नमक या दाल नहीं पहुंची। प्रत्येक जरूरतमंद तक यह सामग्री पहुंची। पहले व्यवस्था में नीयत खराब होने के कारण कार्य नहीं हो पाता था, जिसका खामियाजा उचित दर विक्रेताओं को भुगतना पड़ता था। विभाग का प्रस्ताव आते ही सरकार द्वारा उचित दर विक्रेताओं की मार्जिन मनी बढ़ाने की कार्यवाही की गई है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले अन्नदाता किसानों से लिए जाने वाले खाद्यान्न में व्यापक हेराफेरी होती थी। अन्नदाता किसानों से सीधे खरीद नहीं होती थी और बीच में मीडिएटर होता था। परिणामस्वरूप अन्नदाता किसानों को एम0एस0पी0 का लाभ नहीं मिल पाता था। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि सीधे किसानों से उनकी उपज की खरीद की जाएगी। इससे एम0एस0पी0 का लाभ किसानों को मिलेगा। वर्ष 2017 से राज्य सरकार द्वारा इस प्रक्रिया को लगातार सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया गया है। आज धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, मोटे अनाज आदि की खरीद सीधे अन्नदाता किसानों से जा रही है। डी0बी0टी0 के माध्यम से उपज का उचित मूल्य सीधे किसानों के खाते में दी जा रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में सुधारात्मक कार्य कराये गये हैं। इन विद्यालयों में अच्छी फ्लोरिंग करायी गयी है। सरकार बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग टॉयलेट, पेयजल, स्मार्ट क्लास, फर्नीचर, डिजिटल लाइब्रेरी आदि का निर्माण करा रही है। 1.60 करोड़ बच्चों को बैग, पाठ्य-पुस्तकें, यूनीफॉर्म, जूते-मोजे, स्वेटर सहित अनेक सुविधाएं उपलब्ध करायी रही है। वर्ष 2017 से पूर्व इन विद्यालयों में भवनों का आभाव था। यदि भवन था, तो शिक्षक नहीं, शिक्षक थे तो छात्र नहीं। पेयजल, टॉयलेट जैसी सुविधाएं न होने के कारण सत्र पूरा होने से पहले ही आधे बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते थे। अब निपुण भारत अभियान के अन्तर्गत स्कूली बच्चे अक्षर ज्ञान के साथ ही वाक्य विन्यास में भी पारंगत हुए हैं। विज्ञान, अंग्रेजी, गणित आदि विषयों की शिक्षा विद्यालयों में प्राप्त कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री जी ने आयोजित कार्यक्रम में उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष तथा वर्चुअली जुड़े लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य व श्री ब्रजेश पाठक, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री मनोज पाण्डेय तथा खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री श्री सतीश चन्द्र शर्मा ने भी सम्बोधित किया।

मुख्यमंत्री जी को इस लाभांश वृद्धि हेतु उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला परिषद के अध्यक्ष, ऑल इण्डिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोशिएशन, उपभोक्ता वेलफेयर एसोशिएशन के प्रतिनिधि तथा आदर्श उचित दर विक्रेता ने धन्यवाद पत्र सौंपा।

कार्यक्रम में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं तथा उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया।

इस अवसर पर सांसद श्री बृजलाल, विधान परिषद सदस्य डॉ० लाल जी प्रसाद निर्मल, श्री रामचन्द्र प्रधान, श्री मुकेश शर्मा, विधायक श्री नीरज बोरा, श्री योगेश शुक्ला, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खर्कवाल सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।